

### **ग्र**साबारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उपसण्ड (i)

PART II---Section 3---Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76]

नई विल्ली, बुकतार, मार्च 11, 1977 फाल्गुन 20, 1898

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 1977/PHALGUNA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या दो जातो है जिस ने कि यह ग्रलग सकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed

as a separate compilation.

#### DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

#### NOTIFICATIONS

#### Customs

New Delhi, the 11th March 1977

G S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cows, herers, bulls, goat, sheep and pigs falling under Chapter 1 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India for the purpose of breeding only, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule and the whole of the auxiliary duty of Customs leviable under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

Provided that the importer shall, before an order for clearance for home consumption is passed by the proper officer, produce a certificate from the Department of Agriculture (Ministry of Agriculture and Irrigation) to the effect that—

(1) the animals are being imported for breedings,

- (2) the import is a part of breeding plan duly approved by the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Central Government;
- (3) the animals comply with health requirements as laid down under the live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898); and
- (4) the number of animals imported and the minimum standard of production potential are approved by the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Central Government

[No. 32/F. No. 355/198/76-Cus. I]

# राजस्व ग्रीर बैकिंग विभाग

(राजस्व पका)

प्रधिसूचनाए

## सीमा-शुल्क

नई विल्ली, 11 मार्च, 1977

सा० का० नि० 111(म).--केन्द्रीय सरकार, वित्त मिर्मित्यम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क मिर्मित्यम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना श्रावण्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम भनुसूची के भ्रष्ट्याय 1 के श्रन्तर्गत सम्मिलित गायों, कलोरों, सांखों, बकरियों, भेडो भौर सुभरों को जब उनका भ्रायात भारत में केवल प्रजनन के प्रयोजन के लिए ही किया जाए, उक्त प्रथम भनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क में भ्रीर उक्त वित्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के भ्रधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है:

परन्तु श्रायातकर्ता, समुचित श्रधिकारी द्वारा देश के भीतर उपयोग के लिए निकासी श्रावेश पारित करने से पूर्व, कृषि विभाग (कृषि श्रौर सिचाई मंत्रालय) से निम्नलिखित श्राशय का प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करेगा—

- (1) यह कि पशुभों का भायात प्रजनन के लिए किया जा रहा है;
- (2) यह कि भ्रायात केन्द्रीय सरकार के कृषि श्रौर सिंचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग द्वारा सम्यकरूप से श्रनुमोदित प्रजनन योजना का ही एक भाग है ;
- (3) यह कि पशु, पशुधन भ्रायात श्रधिनियम, 1898 (1898 का 9) के श्रधीन श्रधि-कथित स्वास्थ्य-श्रपेक्षाश्रो के श्रनुरूप हैं ; ग्रीर
- (4) ग्रायात किए गए पशुभों की संख्या और उनकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता केन्द्रीय सरकार के कृषि भौर सिंचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग द्वारा श्रनुमोदित की गई है।

[सं० 32 फा० सं० 355/198 76-सी० मु० ]]

- GSR. 112 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 32 of the Finance Act, 1976 (66 of 1976) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts synthetic industrial diamonds (including boait), falling within Chapter 71 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from—
  - (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent ad valorem; and
  - (b) the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 32 of the said Finance Act.

[No 33/F No 255/216/76-Cus I]

सा० का० नि०112(क्र).—केन्द्रीय मरकार, वित्त अधिनियम, 1976 (1976 का 66) की धारा 32 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा गुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-गुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत सम्मिनित कृतिम औद्योगिक हीरों (इसमें बोर्त भी है) को जब उनका आयात भारत में किया जाए—

- (क) उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो उक्त प्रथम ग्रमुसूची मे विनिर्दिष्ट है ग्रीर जो मूल्य के 40 प्रतिशत से ग्राधिक है; ग्रीर
- (ख) उक्त वित्त श्रधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के श्रधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से छूट देती है।

सिं० 33 फा० मं० 355 216 76-सी ग्-I]

G.S.R. 113 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interests so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No 202-Customs, dated the 24th August, 1963, namely—

In paragraph 2 of the said notification-

- (i) in condition (b), the word "or" shall be inserted at the end;
- (ii) after condition (b) as so amended, the following condition shall be inserted, namely:—-
  - "(c) the vessel belongs to or is chartered by, or engaged on behalf of, the Central Government or a State Government".

[No. 34/F No 355/13/77-Cus I(M)]

M. JAYARAMAN, Under Secv.

सा०का०नि० 113 (ग्र).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुस्क ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना ग्रावश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंद्रालय (राजस्व विभाग) की ग्रिधि-सूचना सं० 202 सीमा-शुल्क, तारीख 24 ग्रगस्त, 1963 में निम्नलिखित ग्रौर संशोधन करती है, ग्रावित :—

उक्त धिसूचना के पैरा 2 में,---

(i) गर्त (खा) में प्रन्त में "या" णब्द जोडा जाएगा ;

- (ii) इस प्रकार संशोधित शर्त (ख) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त प्रत्यापित की जाएगी, प्रश्नात् :---
  - "(ग) जलयान केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का है, या उसके द्वारा भाडे पर लिया गया है, ग्रथवा उसकी ग्रोर से रखा गया है।"।

[स॰ 34 फा॰ सं॰ 355 13/77-सी॰ शु॰ I (एम) J

एम० जयरामन ग्रवर सचिव।